

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- देहरादून दिनांक: 15 अक्टूबर, 2015
वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22 एवं 31 हेतु विभिन्न योजनाओं
हेतु राज्य आकास्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-3673/01 बजट-11(प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव)/2015-16 दिनांक 12-10-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य आकास्मिकता निधि के माध्यम से ₹ 175.00 करोड़ की धनराशि निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश सं०-6931/111(2)/15-05(बजट)/2013टी०सी०-1 दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) पर उल्लिखित शर्त को इस आधार पर संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है कि खण्डवार/योजनावार स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष कार्यवार सी०सी०एल० आवंटन के कारण विभागीय खण्डों के सम्मुख लघु एवं छोटे कार्यों तथा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत कार्यों के लिये धनावंटन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2- अतः आपके द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०-6931/111(2)/15-05(बजट)/2013टी०सी०-1 दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) में उल्लिखित शर्त को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की माननीय श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	शासनादेश दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) में उल्लिखित शर्त का विवरण	शासनादेश दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) में उल्लिखित शर्त को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा।
01	" स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सी०सी०एल० आवंटन, खण्डवार/योजनावार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, दो किशतों में किया जायेगा। प्रथम किशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किशत का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। "	"स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सी०सी०एल० आवंटन, खण्डवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, दो किशतों में किया जायेगा। प्रथम किशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किशत के रूप में खण्डों को एकमुश्त आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। "

3- सन्दर्भित शासनादेश में उक्तानुसार किये जा रहे संशोधन को खण्डवार द्वितीय किशत की सी०सी०एल० आवंटन किये जाने की तिथि से लागू समझा जायेगा।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24-09-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, शासनादेश में उल्लिखित अवशेष शर्तें यथावत् रहेंगी।